

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल
उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक

28

जून, 2017

विषय:- निलम्बनकाल के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा के दौरान गम्भीर दुराचरण करने के परिणामस्वरूप लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुशासन अपील नियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है। कभी-कभी गम्भीर दुराचरण की स्थिति में कतिपय लोक सेवकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व निलम्बित भी किया जाता है। अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने पर आरोपों के प्रमाणित होने की दशा में सम्बन्धित लोक सेवकों को वृहद्/लघु दण्ड भी दिया जाता है और कभी-कभी आरोप प्रमाणित न होने की स्थिति में ऐसे लोक सेवकों को बिना किसी दण्ड के सेवा में बहाल किया जाता है।

2- प्रायः यह देखने में आया है कि लोक सेवकों को जब अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दण्ड दिया जाता है तो उनके निलम्बनकाल के वेतन भत्तों के संबंध में विभागों द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही नहीं की जाती है विभागों द्वारा दण्डादेश में ही निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में उल्लेख कर दिया जाता है और कतिपय विभागों द्वारा निलम्बनकाल के वेतन भत्तों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है यह स्थिति उचित नहीं है।

3- लोक सेवकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान निलम्बित किये जाने और उसके बाद अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने की स्थिति में निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में मूल नियम-54(3) में निम्न प्राविधान किये गये हैं:-

"जहां पुनः पदस्थ करने का आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि निलम्बन बिलकुल ही न्याय संगत नहीं था वहां सरकारी सेवक को उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा जिसके लिए वह हकदार होता, यदि वह निलम्बित न किया गया हो। परन्तु जहां ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाहियों की समाप्ति में प्रत्यक्षतः सरकारी सेवक के कारण विलम्ब हुआ है, वहां वह सरकारी सेवकों अपना अभ्यावेदन देने का अवसर देने के पश्चात और उसके प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकता है कि सरकारी सेवक को ऐसी विलम्ब अवधि के लिये केवल ऐसे वेतन और भत्ते की उतनी राशि (जो सम्पूर्ण राशि न हो) दी जायेगी जितनी वह अवधारित करें।"

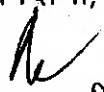
इसी प्रकार अनुशासन अपील नियमावली, 2003 के नियम-5 में निम्न प्राविधान किया गया है:-

"इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनैन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टकरण मांगने के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।"

4- शासन के संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। मूल नियम-54 की व्यवस्था से स्पष्ट है जहां लोक सेवकों विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के समाप्त हो जाती है वहां ऐसे लोक सेवकों को निलम्बनकाल के समस्त वेतन भत्ते अनुमन्य होते हैं उसी प्रकार जैसे कि वह निलम्बित न किया गया हो। परन्तु जहां पर अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी लोक सेवक को आरोपों के किन्ही भाग प्रमाणित होने की स्थिति में दण्ड दिया जाता है वहां पर दण्डादेश निर्गत करने के बाद ऐसे लोक सेवक को मूल नियम-54 की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से कारण बताओ नोटिस दिये जाते हैं। कारण बताओ नोटिस का संबंधित लोक सेवक का उत्तर देने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि क्या निलम्बनकाल के सम्पूर्ण वेतन भत्ते दिये जायें अथवा न दिये जायें और ऐसे

कारणों का उल्लेख करते हुए पृथक से आदेश निर्गत किये जाते हैं। दण्डादेश में निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि निलम्बनकाल और निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय दण्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि उस अवधि में संबंधित लोक सेवक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया होता है इसलिये निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में मूल नियम-54 के अन्तर्गत निर्णय लिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि मूल नियम-54 के अन्तर्गत दण्ड दिये जाने की स्थिति में लोक सेवक को कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक है और उसका सांविधिक बल है।

5— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी भी लोक सेवक के निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव